



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 01, 2019/आश्विन 9, 1941

No. 313]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 01, 2019/ASVINA 9, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2019

मामला सं. 12/20190

**विषय :** चीन जन.गण., मलेशिया और वियतनाम के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सभी रूपों में कोलीन क्लोराइड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

**फा. सं. 6/18/2019—डी जी टी आर.**—यतः मै. जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लि. (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां इसके बाद नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां इसके बाद प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, यूरोपीय संघ और वियतनाम से "सभी रूपों में कोलीन क्लोराइड" (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) या संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और यतः प्रथम दृष्टया यह कि चीन जन.गण., मलेशिया और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त हैं जो पाटनरोधी जांच को उचित ठहराते हैं, इसलिए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के संबंध में जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की

सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

3. प्राधिकारी प्रथम दृष्टया पाते हैं कि यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तु के आयातों का पाटन मार्जिन जांच अवधि के दौरान न्यूनतम सीमा से कम है और क्षति मार्जिन ऋणात्मक है। तदनुसार, यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू नहीं की जा रही है।

#### **क. विचाराधीन उत्पाद**

4. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद सभी रूपों में कोलीन क्लोराइड है। कोलीन क्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है और चतुर्थ अमोनियम साल्ट है जिसका प्रयोग पशु के चारे के अभिवर्धन के रूप में किया जाता है। कोलीन क्लोराइड को विभिन्न रूपों जैसे कॉर्न कॉब, सिलिका और जलीय विलियनों के रूप में उत्पादित किया जाता है।
5. कोलीन क्लोराइड को प्रतिक्रिया के दो स्तरों में उत्पादित किया जाता है जिनमें पहला ट्राइ-मिथाइल एमाइन, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल से प्रतिक्रिया करता है जिसमें एक सॉल्ट (ट्राइ मिथाइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड) बनता है, जो बाद में एथिलिन ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता है और कोलीन क्लोराइड बनाता है। इसके प्रमुख प्रयोगों में पशुओं के चारे में अभिवर्धक, भेषज अनुप्रयोगों, खाद्य प्रयोग और तेल का गैस प्रयोग शामिल हैं। वर्तमान आवेदन केवल कोलीन क्लोराइड के पशु चारे तथा तेल व गैस प्रयोग से संबंधित है।
6. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 23099010, 23099020, 23099090 और 29231000 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

#### **ख. समान वस्तु**

7. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

#### **ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

8. यह आवेदन मै. जुबीलेंट लाइफ साइंसेज लि. द्वारा विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में दायर किया गया है। आवेदक के अनुसार, वे भारत में संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादक हैं। आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के कोई आयात नहीं किए हैं या उनका संबद्ध देश में कोई संबंधित पक्ष नहीं है।
9. प्राधिकारी प्रथमदृष्टया निर्धारित करते हैं कि आवेदक का कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है और वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं।

#### **घ. संबद्ध देश**

10. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन गण, मलेशिया और वियतनाम हैं।

#### **ड. सामान्य मूल्य**

11. सभी संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन भारत में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों तथा तर्कसंगत लाभ से जोड़कर किया गया है।

**च. निर्यात कीमत**

12. आवेदक ने डी जी सी आई एंड एस, द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार निर्यात कीमत का परिकलन किया है। कमीशन, समद्री भाड़ा, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय माल भाड़े, समुद्री बीमा, गैर-वापसी योग्य वैट (केवल चीन के लिए) और बैंक प्रभारों के कारण कीमत समायोजन का दावा किया गया है।

**छ. पाटन मार्जिन**

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथमदृष्टया संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में उल्लेखनीय भारी पाटन मार्जिन को दर्शाता है। इसके प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु पाटित की जा रही हैं।

**ज. क्षति और कारणात्मक संबंध**

14. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर घरेलू उद्योग की क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने कुल रूप में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप सामना की गई क्षति तथा भारत में उत्पादन और खपत, कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद लाभ (नकद प्रवाह), माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता आदि के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

**झ. जांच की अवधि**

15. याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 2018 से जून, 2019 (15 महीने) तक वर्तमान जांच करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, क्षति जांच अवधि 2015-16, 2016-17, 2017-2018 और जांच अवधि शामिल होगी।

**ञ. समय सीमा**

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरूआत की सूचना देने वाले पत्र जारी करने की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

**ट. सूचना प्रस्तुत करना**

17. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से प्राधिकारी को संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

महानिदेशक

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध ऊपर दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

**ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

19. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।
20. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
21. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
22. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
23. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
24. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

25. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

**ढ. असहयोग**

26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**INTIMATION NOTIFICATION**

New Delhi the 1st October, 2019

Case No. 12/2019

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Choline Chloride in all forms" originating in or exported from China PR, Malaysia and Vietnam.**

**F. No. 6/18/2019- DGTR.**— Whereas, M/s. Jubilant Life Sciences Ltd (hereinafter also referred to as the Petitioner or Applicant) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as

the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of "Choline Chloride in all its form" (hereinafter also referred to as the Product under consideration (PUC) or subject goods) from People's Republic of China, Malaysia, European Union and Vietnam.

2. And whereas, on finding prima facie that evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR, Malaysia and Vietnam (hereinafter as "the subject countries"), injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
3. The Authority has prima facie found that the dumping margin on imports of subject goods from European Union is *de-minimus* and the injury margin negative for the period of investigation. The anti-dumping investigation accordingly is not being initiated concerning imports originating in or exported from European Union.

**A. Product under consideration**

4. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Choline Chloride in all its form". Choline Chloride is an organic compound and a quaternary ammonium salt used as an additive in animal feed. Choline Chloride can be produced in various forms, such as corn cob, on silica and in aqueous solutions.
5. Choline Chloride is produced in two stages of reaction process; wherein, first, Trimethyl Amine reacts with Hydrochloric Acid, to form a salt (Trimethyl Amine Hydrochloride); which then reacts with Ethylene Oxide to give Choline Chloride. The major applications include additive in animal feed, pharma applications, food application and Oil & Gas Applications. Present application concerns only the Choline Chloride with animal feed & oil and gas applications.
6. The subject goods are classified under customs tariff heading 23099010, 23099020, 23099090 and 29231000. The customs classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

**B. Like Article**

7. The applicants have claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The applicants have further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry in India is treated as the 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

**C. Domestic Industry & Standing**

8. The Application has been filed by M/s. Jubilant Life Sciences Ltd as domestic producers of the product under consideration. According to the applicant, they are the major producers of the subject goods in India. The applicants have certified that there are no imports of the product under consideration by the applicants or any of its related party from the subject countries.

9. The Authority prima facie determines that the applicant holds a “major proportion” of the total domestic production and thereby constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Anti-Dumping Rules.

**D. Subject Countries**

10. The countries involved in the present investigation are China PR, Malaysia and Vietnam.

**E. Normal Value**

11. Normal value for all the subject countries has been constructed on the basis of cost of production of domestic industry in India, duly adjusted, and after additions for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

**F. Export Price**

12. The applicants have computed the export price on the basis of data published by DGCI&S. Price adjustments have been claimed on account of commission, ocean freight, port expenses, inland freight, marine insurance, non-refundable VAT (only for China) and bank charges.

**G. Dumping Margin**

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie show significant dumping margin in respect of the subject goods from the subject countries, thereby, indicating prima facie that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

**H. Injury and Causal Link**

14. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, price suppression, capacity utilization, factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping, cash profit (cash flow), inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments etc.

**I. Period of Investigation**

15. The petitioner has proposed a present investigation from April, 2018 to June, 2019 (15 months). The injury investigation will, however, cover the periods 2015-16, 2016-17, 2017-2018 and POI.

**J. Time Limit**

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose or otherwise of the anti-dumping measures within 40 days from the date of issue of letter by the authority intimating initiation of the investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

**K. Submission of Information**

17. The exporters in the subject countries, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Director General**  
**Directorate General of Trade Remedies,**  
**Jeevan Tara Building, 4th Floor**  
**5, Parliament Street, New Delhi -110001**

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out above. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**L. Submission of Information on Confidential Basis**

19. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
20. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non- confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (2) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
21. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
23. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**M. Inspection of Public File**

25. In terms of Rule 6(7) of the Anti-Dumping Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**N. Non-cooperation**

26. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority